Important!

Office of the

Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Uttarakhand

(Van Bhawan, 85/87 Rajpur Road, Dehradun, Mail ID-pccfuk@gmail.com)

Letter No. P.O. / 1047 Dehradun Dated: 15 February, 2020

Report before The National Green Tribunal, New Delhi
(In compliance of Hon'ble National Green Tribunal direction dated 16.01.2020 issued in O.A. No. 01/2020)

That earlier the same petitioner had filed O.A. No. 223/2019 before the Hon'ble National Green Tribunal with the prayer to restrain construction being made by Uttarakhand Tourism Development Board in forest land in *Park Estate Hathipaon, Mussoorie, Dehradun* without approval under Forest (Conservation) Act, 1980. The Hon'ble National Green Tribunal vide its order dated 21.02.2019 directed the Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Uttarakhand to submit a factual report. The Principal Chief Conservator of Forests (HoFF) vide his letter dated 19.09.2019 submitted the following report: -

> ***"That in compliance of the Hon'ble National Green Tribunal order dated 21.02.2019, the Divisional Forest Officer, Mussoorie Forest Division was directed to submit a factual report. The Divisional Forest Officer, Mussoorie Forest Division has submitted the latest report in the matter vide letter no. 1152/29-1 dated 19.09.2019 to this office. As reported, it is to inform that at present the ruins of old buildings and old road of George Everest area under Park Estate, Hathipaon (notified as private forest estate) which were existing before year 1980 are being reconstructed and renovated by the Uttarakhand Tourism Department in consultation with the Uttarakhand Tourism Development Board. The permission for reconstruction and renovation of works was granted by the State Government under the rules stipulated by Ministry of Environment and Forest, Govt. of India (in the light of directives of the Hon'ble Supreme Court of India) vide letter no. 11-1/98-FC(pt) dated 28.02.2001. No new construction being done."***

In the light of the above quoted report O.A. No. 223/2019 was disposed of by this Hon'ble Tribunal vide order dated 20.09.2019.

That this present second Original Application No. 01/2020 (Mrs. Bharti Kawatra vs. Uttarakhand Tourism Development Board and others) with the same prayer has been filed before the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi. The Hon'ble Tribunal vide its order dated 16.01.2020 issued the following order: -

"1. Grievance in this application is that illegal construction activity is being undertaken in forest area without requisite approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 at Park Estate, Hathipaon, Mussoorie, Dehradun District.

2. It is stated that the same issue was earlier raised in O.A. No. 223/2019, Mrs. Bharti Kawatra vs. Department of Tourism Uttarakhand & Ors. Which was disposed of on 20.09.2019. In view of the report that no construction was being done and only renovation of the building was being done which was not in forest land. It is stated that now illegal construction is taking place as shown by the photographs annexed. Road is being widened which amounts to new construction which will lead to destruction of rocks, cutting of trees, cause soil erosion, landslides and flood. Adverse impact on ecology and environment is being ignored for commercial benefit of Uttarakhand Tourism Development Board.

3. Without expressing any opinion on merits at this stage, we consider it necessary to require a factual and action taken report in the matter from the PCCF (HoFF), Uttarakhand. Let the same be furnished within one month by e-mail at……. "

That in compliance of the Hon'ble National Green Tribunal order dated 16.01.2020 the Divisional Forest Officer, Mussoorie Forest Division was directed to submit a factual report.

The Divisional Forest Officer, Mussoorie Forest Division directed the Range Officer to conduct a joint inspection along with the Officers of the Municipal Corporation, Mussoorie. The joint inspection team conducted the inspection on 30.01.2020.

The Divisional Forest Officer, Mussoorie Forest Division has submitted the latest report in the matter vide letter no 3314/29-3 dated 07.02.2020 which was received on 13.02.2020. As reported it is informed that: -

- At present the old ruined C.C. Road which is in existence from 1943 (as per Municipal Corporation, Mussoorie records) has been renovated. No new construction of road or widening of road or any felling of trees have taken place.

- At present the renovation work of old building namely George Everest Heritage Building is being done. No new construction is taking place at the site.

That the Municipal Corporation has also issued a certificate stating that renovation of old building and old existing motor road has been done which were in existence prior to 1980. Similarly a certificate is also issued by Uttarakhand Tourism Development Board stating that the old road which was is existence has been renovated and for this purpose no felling of trees and no widening of road has taken place. The Uttarakhand Tourism Development Board is respondent no. 1 in the present Original Application No. 01/2020.

The permission for reconstruction and renovation of works was granted by the State Government under the rules stipulated by Ministry of Environment and Forest, Govt. of India (in the light of directives of the Hon'ble Supreme Court of India) vide letter no. 11-1/98-FC(pt) dated 28.02.2001. No new construction being done.

Thanking You

<u>Enclosures</u> : -

1. Copy of DFO letter no. 3314/29-3 dated 07.02.2020 along with Joint Inspection Report and certificates issued by Nagar Palika Parishad, Mussoorie (Municipal Board, Mussoorie) and Project Management Unit (Uttarakhand Tourism Development Board)
2. Copy of Ministry of Environment and Forest, Govt. of India letter no. 11-1/98-FC(pt) dated 28.02.2001.

(Jai Raj)
PCCF (HoFF),
Uttarakhand, Dehradun.

61

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक–3315 /29–3 दिनांकः मसूरी, 07 फरवरी, 2020

सेवा में,,

प्रमुख वन संरक्षक (HOFF)
उत्तराखण्ड,देहरादून।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र ओ0ए0 नं0 01/ 2020 श्रीमती भारती क्वात्रा बनाम उत्तराखण्ड पर्यटन विभाग व अन्य।

महोदय,

श्रीमती भारती क्वात्रा ने मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में भारती क्वात्रा बनाम उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद व अन्य माह दिसम्बर 2019 दाखिल की गयी है। मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली ने प्रार्थना पत्र पर दिनांक 16 जनवरी 2020 को सुनवाई करते हुए प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए एक माह के अन्दर अनुपालन सूचना उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा याचीकर्ती के पूर्व शिकायती पत्र मा0 न्यायालय में मूल प्रार्थना पत्र संख्या 223/2019 के रूप में पंजीबद्ध हुआ था, का निस्तारण दिनांक 19–9–2019 को किया गया। किन्तु याचीकर्ती के द्वारा भ्रामक बिन्दुओं के आधार पर पुनः शिकायती बिन्दुओं में उल्लेख किया गया कि प्रतिपक्षीगण संख्या –3 (प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड देहरादून के द्वारा मा0 न्यायालय में दिनांक 19–9–2019 को (ATR) शपथ पत्र में उल्लेख किया मौके पर नये निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है किन्तु पुरानी संरचनाओं में जीर्णोद्धार किया जा रहा है तथा तथाकथित स्थल वन भूमि नहीं है। श्रीमती भारत क्वात्रा ने प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड महोदय, द्वारा दिये गये शपथ पत्र पर असहमति व्यक्त करते हुए शिकायत बिन्दु में उल्लेख किया है " जबकि वास्तविकता यह है कि मौके पर पुराना मार्ग संर्किण पैदल चलने वाला था जो चौड़ा करके मोटर मार्ग के रूप मे कंक्रीट द्वारा बनाया जा रहा है, जिसके कारण मौके पर नया खुदान कर रोड़ चौडीकरण किया गया है तथा प्राकृतिक चट्टानों को काटा जा रहा है, वृक्षों का पातन किया जा रहा है जिससे पर्यावरणीय स्थलीय पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना बढ़ रही है तथा मौके पर पर्यटन विकास परिषद द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजन से पार्क इस्टैट को विकसित करने से प्रदूषण एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का उल्लेख भी किया गया है। "

इसी संदर्भ में याचीकर्ती के द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में दिये गये प्रार्थना पत्र में उल्लिखित शिकायत बिन्दुओं पर वन क्षेत्राधिकारी, मसूरी को स्थलीय जांच रिपोर्ट

Scanned by CamScanner

उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 3144 / 29–3 दिनांक 28–01–2020 से निर्देश दिये गये (छाया प्रति संलग्नक–1)।

वन क्षेत्राधिकारी मसूरी ने अपने पत्रांक 804 / 21–3 दि0 31–01–2020 (छाया प्रति संलग्नक– 2) द्वारा सूचित किया है कि श्रीमती भारती क्वात्रा की शिकायत बिन्दुओं पर दिनांक 30.01.2020 तक की अध्यावधिक स्थिति के आधार पर मसूरी नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत पार्क इस्टेट ह्राथीपांव, मसूरी अन्तर्गत पर्यटन विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का खुदान व गैर वानिकी कार्य नहीं करवाया जा रहा है। स्थलीय निरीक्षण वन वन क्षेत्राधिकारी, मसूरी रेंज, संबंधित क्षेत्र के वन दरोगा, वन बीट अधिकारी तथा नगरपालिका परिषद, मसूरी के प्रतिनिधि श्री आदित्य शाह, मानचित्रकार दिनांक 30–01–2020 को उपस्थित थे। स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित विवरण निम्न प्रकार है:–

(1) जार्ज एवरेस्ट पहुँच मार्ग से पुराने बने क्षतिग्रस्त सी0सी0 मार्ग पर पुनः सी0सी0 कार्य किया पाया गया, इसके अतिरिक्त मार्ग में कोई अतिरिक्त खुदान नहीं पाया गया और ना ही किसी वृक्ष का पातन पाया गया है। उक्त मार्ग नगर पालिका परिषद् मसूरी की सूचना के अनुसार 1943 से पूर्व का बना हुआ है। नगर पालिका परिषद का पत्र संलग्न है।

(2) जार्ज एवरेस्ट हैरिटेज बिल्डिंग का जीर्णोद्वार किया जा रहा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त नगर पालिका परिषद् मसूरी ने पत्र संख्या 2736 / E O दिनांक 7–2–2020 (छाया प्रति संलग्नक–3) के द्वारा निम्न प्रकार प्रमाण पत्र दिया गया है:–

"प्रमाणित किया जाता है कि मसूरी क्षेत्रान्तर्गत उत्तराखण्ड पर्यटन विभाग की स्वामित्व वाली भूमि पार्क स्टेट के जार्ज हाऊस एसरेस्ट में पुरानी भवन संरचनाओं जो कि वर्ष 1980 से पूर्व की है, में पुनः निर्माण कार्य जॉर्ज हाऊस को जाने वाला सी0सी0 क्षतिग्रस्त मार्ग पर सी0सी0 का कार्य पर्यटन विभाग द्वारा किया / कराया जा रहा है। यह मार्ग 1980 से पूर्व का है, इस मार्ग पर कोई अतिरिक्त खुदान / चौड़ीकरण नहीं किया गया है और वतर्4मान में किसी प्रकार का कोई वन निर्माण कार्य नहीं हुआ है। "

अपर कार्यक्रम निदेशक, परियोजना प्रबन्धन इकाई, पर्यटन संरचना विकास निवेश कार्यक्रम, उत्तराखण्ड शासन ने अपने पत्र संख्या 8792 / 2–10 / ए0डी0बी0 / आई0डी0आई0पी0टी0 / 415 / 2019–20 दिनांक 30–01–2020 (छाया प्रति संलग्नक– 4) के द्वारा सूचित किया गया है कि "जार्ज एवरेस्ट हेरिटेज पार्क में स्थित सड़क में बैस लेयर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है जिसमें किसी भी वृक्ष की कटाई नहीं की गई है तथा सड़क का निर्माण पूर्व में बनी सड़क के ऊपर बिना चौड़ीकरण के किया गया है। "

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि जार्ज एवरेस्ट पहुँच मार्ग तीव्र ढलान में अवस्थित है तथा प्रत्येक वर्ष भारी वर्षात के बाद उक्त मार्ग जगह–जगह से टूटने के कारण उसी मार्ग के ऊपर सी0सी0 आदि कार्य के लिए नगर पालिका परिषद तथा वन विभाग से वन (संरक्षण)

Scanned by CamScanner

अधिनियम, 1980 के तहत अनुमति मांगने उपरान्त पर्यटन विकास परिषद् के स्तर से तथाकथित मार्ग को बिना चौड़ीकरण के गढ्डे, टूट–फूट आदि मरम्मत आदि कार्य प्रति वर्ष करवाया जाता है।

सर्वे आफ इण्डिया द्वारा पार्क इस्टेट का सर्वेक्षण कार्य किया जा चुका है जिसमें 149 मुनारे सर्वे आफ इण्डिया द्वारा चिन्हित स्थानो पर वन विभाग द्वारा स्थापित किये जा चुके हैं। पर्यटन विभाग द्वारा वन भूमि पर किये जाने वाले गैर वानिकी कार्य जो मसूरी वन्यजीव विहार के क्षेत्र से बाहर तथा ईको सेन्सिटिव जोन में भी प्रस्तावित नहीं है। पर्यटन विभाग द्वारा भारत सरकार की पूर्वानुमति हेतु प्रस्ताव स्वीकृति हेतु कार्यवाही गतिमान चल रही है। भारत सरकार से प्रस्ताव विधिवत स्वीकृति अभी प्राप्त नही हुयी है। इसी संदर्भ में अपर सचिव, वन अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के स्तर से शासकीय पत्र सवंख्या 89 / **X-3-20 / 1 (11) / 2020** दिनांक 29–1–2020 **(छाया प्रति संलग्नक– 5)** के द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,25 सुभाष रोड़, उत्तराखाण्ड, देहरादून को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के तहत स्वीकृति प्रदान करने के लिए पत्र लिखा गया है।

उपरोक्तानुसार स्थलीय जांच एवं संगत अभिलेखो के उपरान्त पाया गया है कि मौके पर कोई अवैध पातन नहीं हुआ तथा मार्ग के चौड़ीकरण हेतु चट्टान आदि की ब्लास्टिंग आदि कार्य मौके पर नहीं पाये गये हैं।

अतः स्थलीय आख्या मय अभिलेखों के साथ सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक :– उक्तानुसार।

भवदीया,

(कहकशां नसीम भ0व0से0)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

संख्या /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक (गढवाल) उत्तराखण्ड, पौडी।
3. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(कहकशां नसीम भ0व0से0)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

Scanned by CamScanner

संलग्नक- i

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक–3144 /29–3 दिनांक: मसूरी, 28 जनवरी 2020

सेवा में,

रेंज अधिकारी
मसूरी रेंज।

विषयः– मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा वाद सं0 01/ 2020 में दिनांक 16.01.2020 को पारित निर्णय के सबंध में।

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा वाद सं0 01/ 2020 भारती क्वात्रा बनाम उत्तराखण्ड पर्यटन विभाग व अन्य में दिनांक 16.01.2020 को पारित निर्णय में प्रमुख वन संरक्षक, महोदय द्वारा मा0 न्यायालय के समक्ष ए0टी0आर0 01 माह के अन्दर प्रेषित करने के आदेश निर्गत किये है। उक्त प्रकरण/वाद हाथीपांव पार्क इस्टेट, मसूरी में बिना भारत सरकार की अनुमति के निर्माण कार्य करने के संबंध में है जिसकी आपके द्वारा पूर्व में भी स्थलीय जांच की गयी थी। प्रकरण में श्रीमती भारती क्वात्रा द्वारा बार– बार मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली के समक्ष हाथीपांव पार्क इस्टेट, मसूरी में बिना भारत सरकार की अनुमति के निर्माण कार्य करने के संबंध में शिकायत की जा रही है।

अतः आपको उक्त याचिका की प्रति इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि याचिका का अवलोकन कर वस्तुस्थिति से इस कार्यालय को अवगत करायें। साथ ही प्रकरण में नगर पालिका परिषद मसूरी से सम्पर्क कर उल्लेखित स्थल की संयुक्त स्थलीय जांच करे तथा स्थल में वर्तमान समय में कोई निर्माण कार्य चल रहा है अथवा कोई नव निर्माण संरचना हुयी है से भी इस कार्यालय को अवगत कराते हुये संयुक्त निरीक्षण जांच आख्या 02 दिन ~~सप्ताह~~ के अन्दर प्रेषित करें।

संलग्नक :– उक्तानुसार ।

(कहकशां नसीम भा0व0से0)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

संख्या 3144/तददिनांकित।

प्रतिलिपिः–अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मसूरी को इस अनुरोध के साथ कि प्रकरण में वन क्षेत्राधिकारी मसूरी का अपने स्तर से वांछित सहयोग प्रदान करते हुये हाथीपांव पार्क इस्टेट मसूरी में, वर्ष 1980 से पूर्व निर्मित संरचानाओ के संबंध में प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि मा0 न्यायालय के समक्ष समय से रिपोर्ट प्रेषित की जा सके।

(कहकशां नसीम भा0व0से0)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

01C

Scanned by CamScanner

महत्वपूर्ण
C.c.F. (Legal)
मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन
उत्तराखण्ड
17-1-2020
21 JAN 2020

Item No.10 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No.01/2020

Bharti Kawatra Applicant(s)

Versus

Uttarakhand Tourism Development Board & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 16.01.2020

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE S.P WANGDI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER
HON'BLE MR. SIDDHANTA DAS, EXPERT MEMBER

For Applicant(s): Mr. Pranay Nath Jha and Ms. Simran Soni, Advocates

ORDER

1. Grievance in this application is that illegal construction activity is being undertaken in forest area without requisite approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 at Park Estate, *Hathipaon*, Mussoorie, Dehradun District.

2. It is stated that the same issue was earlier raised in O.A. No. 223/2019, *Mrs. Bharti Kawatra v. Department of Tourism, Uttarakhand & Ors.* which was disposed of on 20.09.2019, in view of the report that no construction was being done and only renovation of the building was being done which was not in forest land. It is stated that now illegal construction is taking place as shown by the photographs annexed. Road is being widened which amounts to new construction which will lead to destruction of rocks, cutting of trees, cause soil erosion,

Scanned by CamScanner

landslides and floods. Adverse impact on ecology and environment is being ignored for commercial benefit of Uttarakhand Tourism Development Board.

3. Without expressing any opinion on merits at this stage, we consider it necessary to require a factual and action taken report in the matter from the PCCF (HoFF), Uttarakhand. Let the same be furnished within one month by e-mail at

A copy of this order be sent to PCCF (HoFF), Uttarakhand by e-mail.

The applicant may furnish set of papers to the PCCF (HoFF), Uttarakhand and file affidavit of service within one week.

List for further consideration on 30.03.2020.

Adarsh Kumar Goel, CP

S.P Wangdi, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

Siddhanta Das, EM

January 16, 2020
Original Application No.01/2020

CCF (Garhwal)
कृ० सही स्थिति से
तुरंत अवगत करायें।
संलग्न क: यथोपरि।
25/01/2020

Scanned by CamScanner

संलग्नक 2

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी, मसूरी राजि, मसूरी।

पत्रांक 804 /29-3, दिनांक,मसूरी, जनवरी, 31 ,2020.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
द्वारा– उप प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग,लाडपुर, देहरादून।

विषय– मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या–01/2020 में दिनांक 16–01–2020 को पारित निर्णय के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक 3144/29–3, दिनांक 28–01–2020.

महोदय,

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या–01/2020 में दिनांक 16–01–2020 को पारित निर्णय के संबंध में हाथीपाव पार्क इस्टेट, मसूरी मे बिना भारत सरकार के अनुमति के निर्माण करने के संबंध में स्थलीय संयुक्त निरीक्षण नगरपालिका परिषद, मसूरी के मानचित्राकार एवं वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति में दिनांक 30–01–2020 को किया गया है। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट मय मूल पत्रावली के आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न – मूल पत्रावली एवं संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट ।

भवदीय,

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज, मसूरी।

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

Scanned by CamScanner

संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट

श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी के आदेश सख्या 3144/29--3, दिनाक 28-01-2020 के अनुपालन म नगर पालिका परिषद मसूरी/वन विभाग के निम्न अधिकारियो/कर्मचारियो की उपस्थिति मे मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा वाद स0-01/2020 दिनाक 16-01-2020 को पारित निर्णय के सबध में हाथीपाव पार्क इस्टेट, मसूरी मे बिना भारत सरकार की अनुमति के निर्माण करने के सबध मे दिनाक 30-01-2020 का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

(1) श्री वीरेन्द्र सिह रावत, वन क्षेत्राधिकारी, मसूरी रेंज।
(2) श्री केसरी चन्द नौटियाल, वन दरोगा, दुधली सैक्शन।
(3) श्री सुरेन्द्र प्रसाद भट्ट, वन बीट अधिकारी, दुधली बीट।
(4) श्री आदित्य शाह, मानचित्रकार, नगरपालिका परिषद, मसूरी।

संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है –

(1) जार्ज एवरेस्ट पहुच मार्ग में पुराने बने क्षतिग्रस्त सी0सी0 मार्ग पर पुनः सी0सी0 कार्य किया पाया गया, इसके अतिरिक्त मार्ग मे कोई अतिरिक्त खुदान नही पाया गया है और ना ही किसी वृक्ष का पातन पाया गया है। उक्त मार्ग 1943 से बना हुआ है, नगर पालिका परिषद, मसूरी का प्रमाण पत्र सलग्न है।

(2) जार्ज एवरस्ट हैरिटेज बिल्डिग का जीर्णोद्वार किया जा रहा है, के अतिरिक्त कोई नव निर्माण कार्य नही किया जा रहा है।

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त आऊट हाऊस स0--1 व 2 का पुर्न निर्माण कार्य मौके पर किया जाना पाया गया है। उक्त आऊट हाऊस भी 1980 से पूर्व की बनी सरचनाओं पर ही किया जा रहा है। उक्त सरचनाये 1980 से पूर्व की है, जिसके सबध में नगर पालिका परिषद, मसूरी का प्रमाण पत्र सलग्न है।

उपरोक्त कार्यो के अतिरिक्त कोई नव निर्माण/अवैध पातन मौके पर नहीं पाया गया है। चूकि उपरोक्त सभी कार्य 1980 से पूर्व की बनी संरचनाओं पर किया जा रहा है जिसमें वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नही पाया गया।

S. P. Bhatt 30/01/2020
(सुरेन्द्र प्रसाद भट्ट)
वन बीट अधिकारी
दुधली बीट।

[signature] 30-1-2020
(केसरी चन्द नौटियाल)
वन दरोगा,
दुधली सेक्शन, मसूरी रेंज।

B. Rawat 30-1-20
(बीरेन्द्र सिंह रावत)
वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज, मसूरी।

[signature]
(आदित्य शाह)
मानचित्रकार,
नगरपालिका परिषद, मसूरी।

मूल में अग्रसारित।
[signature]
S.D.O.

Scanned by CamScanner

कार्यालय नगर पालिका परिषद, मसूरी ।

पत्रांक – /निoविo/2019–20 दिनांक :– 27.05.19

सेवा में,

श्री नरेश नमाला,
वन संरक्षण विशेषज्ञ,
आई0डी0आई0पी0टी0, पर्यटन विभाग,
देहरादून ।

विषय – जार्ज एवरेस्ट मे पहुंच मार्ग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 27–05–2019 के सम्बन्ध मे आपको अवगत कराना है कि पालिका मे उपलब्ध जार्ज ऐबरेस्ट/पार्क स्टेट के वर्ष 1943 के मानचित्रानुसार उक्त मार्ग प्रदर्शित है।

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, मसूरी।

Scanned by CamScanner

Annexure – I

Construction Status of Existing Building Prior to 1980

(617)

कार्यालय नगर पालिका परिषद, मसूरी।

पत्रांक– / नि0वि0 / 2018–19 दिनांक:–

सेवा मे,

निदेशक / कार्यालध्यक्ष,
उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद,
निकट–ओ0एन0जी0सी0 हेलीपैड, नांबूवाला गढीकैन्ट,
देहरादून।

विषय:– जनपद देहरादून के जार्ज एबरेस्ट मसूरी मे पर्यटन विभाग की भूमि पर पर्यटको की सुविधा व पर्यटन विकास के लिए "जार्ज एबरेस्ट विरासत पार्क का विकास" हेतु अनापत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पंत्राक सं0 1671/2-6 401/03 दिनांक 13–08–2018 के द्वारा जार्ज एबरेस्ट विरासत पार्क का विकास हेतु निम्नलिखित दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपि आपको बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है:–

1. प्रमाणित किया जाता है कि जार्ज एबरेस्ट / पार्क हाउस मौजूदा इमारत पालिका अभिलेखो वर्ष 1943 के मानचित्र के अनुसार वर्ष 1980 से पूर्व निर्मित है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि का स्वामित्व वर्तमान मे पालिका के कर विभाग मे मांग सं0 389 / 4 मे उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद, के नाम से दर्ज है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि जार्ज एबरेस्ट भवन का लैण्डयूज पालिका अभिलेखा मे दर्ज नही है।
4. जार्ज एबरेस्ट / पार्क हाउस भूमि के मानचित्र की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

भवदीय

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, मसूरी।

Scanned by CamScanner

कार्यालय नगर पालिका परिषद, मसूरी।

दूरभाष सं0 – 0135–2632251, फैक्स सं0 – 0135–2632039
ई मेल –nppmussoorie@gmail.com

पत्रांक 918/मे0 / अधि0अधि0 / 2018–19, दिनांक 31/8/18

सेवा में,

वन संरक्षक विशेषज्ञ,
उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद,
पं0 दीन दयाल उपाध्याय पर्यटन भवन,
निकट ओ0एन0जी0सी0 हेलीपैड नीबूवाला,
गढ़ी कैन्ट, देहरादून।

विषय :– जनपद देहरादून के जॉर्ज ऐवरेस्ट मसूरी में पर्यटन विभाग की भूमि पर पर्यटकों की सुविधा व पर्यटन विकास के लिये जॉर्ज ऐवरेस्ट विरासत पार्क के विकास हेतु वन विभाग को अनापत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0 – 6747 / 2–10 / ए0डी0बी0 / आई0डी0आई0पी0टी0 / 120 / 2018–19 दिनांक 23–08–2018 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी के मौखिक निर्देशानुसार पालिका मानचित्रकार के द्वारा उपरोक्त स्थल का आज दिनांक 29–08–2018 को पार्क स्टेट (जॉर्ज हाउस) का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरान्त खण्डहर / भवनों की छत, दीवारें क्षतिग्रस्त हो रही है तथा स्थल पर समस्त खण्डहर / भवनों की प्लिंथ का क्षेत्रफल निम्नवत् है :–

1– मुख्य भवन	– 290.00 वर्ग मी0
2– आउट हाउस	– 50.00 वर्ग मी0
3– आउट हाउस	– 74.00 वर्ग मी0
4– आउट हाउस	– 9.00 वर्ग मी0
5– ऑबजरवेटि	– 24.00 वर्ग मी0

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, मसूरी।

Scanned by CamScanner

संलग्नक 3

कार्यालय नगर पालिका परिषद, मसूरी।

दूरभाष सं0 – 0135–2632251, फैक्स सं0 – 0135–2632039
ई मेल –nppmussoorie@gmail.com

पत्रांक 2736/E.O/प्रमाण–पत्र/अ0अ0/2020, दिनांक 07/02/2020

"प्रमाण पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि "मसूरी क्षेत्रान्तर्गत उत्तराखण्ड पर्यटन विभाग की स्वामित्व वाली भूमि पार्क स्टेट के जॉर्ज हाउस एवरेस्ट में पुरानी भवन संरचनाओं जो कि वर्ष 1980 से पूर्व की है, में पुनः निर्माण कार्य एवं जॉर्ज हाऊस को जाने वाला सी0सी0 क्षतिग्रस्त मार्ग पर सी0सी0 का कार्य पर्यटन विभाग द्वारा कराया जा रहा है। यह मार्ग वर्ष 1980 से पूर्व का है, इस मार्ग पर कोई अतिरिक्त खुदान/चौड़ीकरण नहीं किया गया है और ना ही वर्तमान में किसी प्रकार का कोई नव निर्माण कार्य नहीं हुआ है।"

उक्त प्रमाण पत्र अनुभागीय आख्या के आधार पर जारी किया जा रहा है।

अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद, मसूरी।

Scanned by CamScanner

संलग्नक-4

परियोजना प्रबन्धन इकाई
पर्यटन संरचना विकास निवेश कार्यक्रम
(ए0डी0बी0 सहायतित–लोन न 2833 व 3223, इंडिया)
उत्तराखण्ड शासन
पं0दीनदयालउपाध्याय पर्यटनभवन, नियर ओ0एन0जी0सी0 हैलिपैड
गढ़ी कैन्ट, देहरादून– 248003

Govt. of Uttarakhand

Uttarakhand
Simply Heaven!

फोन : 91.135.2559985, फैक्स रू 91.135.2559985
ई–मेल : **utdb.pmu@gmail.com**

8792 /2–10/ए0डी0बी0/आई0डी0आई0पी0टी0/415/2019–20

दिनांकः 30/01/2020

सेवा में,

प्रभागयी वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी
जिला – देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषय– जॉज एवरेस्ट हेरिटेज पार्क में प्रस्तावित पर्यटन विकास के कार्यों के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक मे आपको अवगत कराना है कि ए0डी0बी0 सहायतित "पर्यटन संरचना विकास एवं निवेश कार्यक्रम" के अन्तर्गत मसूरी में पर्यटन विकास हेतु जॉज एवरेस्ट हेरिटेज पार्क का विकास कार्य प्रस्तावित है।

इस संदर्भ में अवगत कराना है कि सड़क में बैस लेयर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है जिसमें किसी भी वृक्ष की कटाई नही की गयी है तथा सड़क का निर्माण पूर्व में बनी सड़क के ऊपर बिना चौड़ीकरण के किया गया है।

30.1.2020
(आर0 के0 तिवारी)
अपर कार्यक्रम निदेशक

D/Man
D.F.O.

Scanned by CamScanner

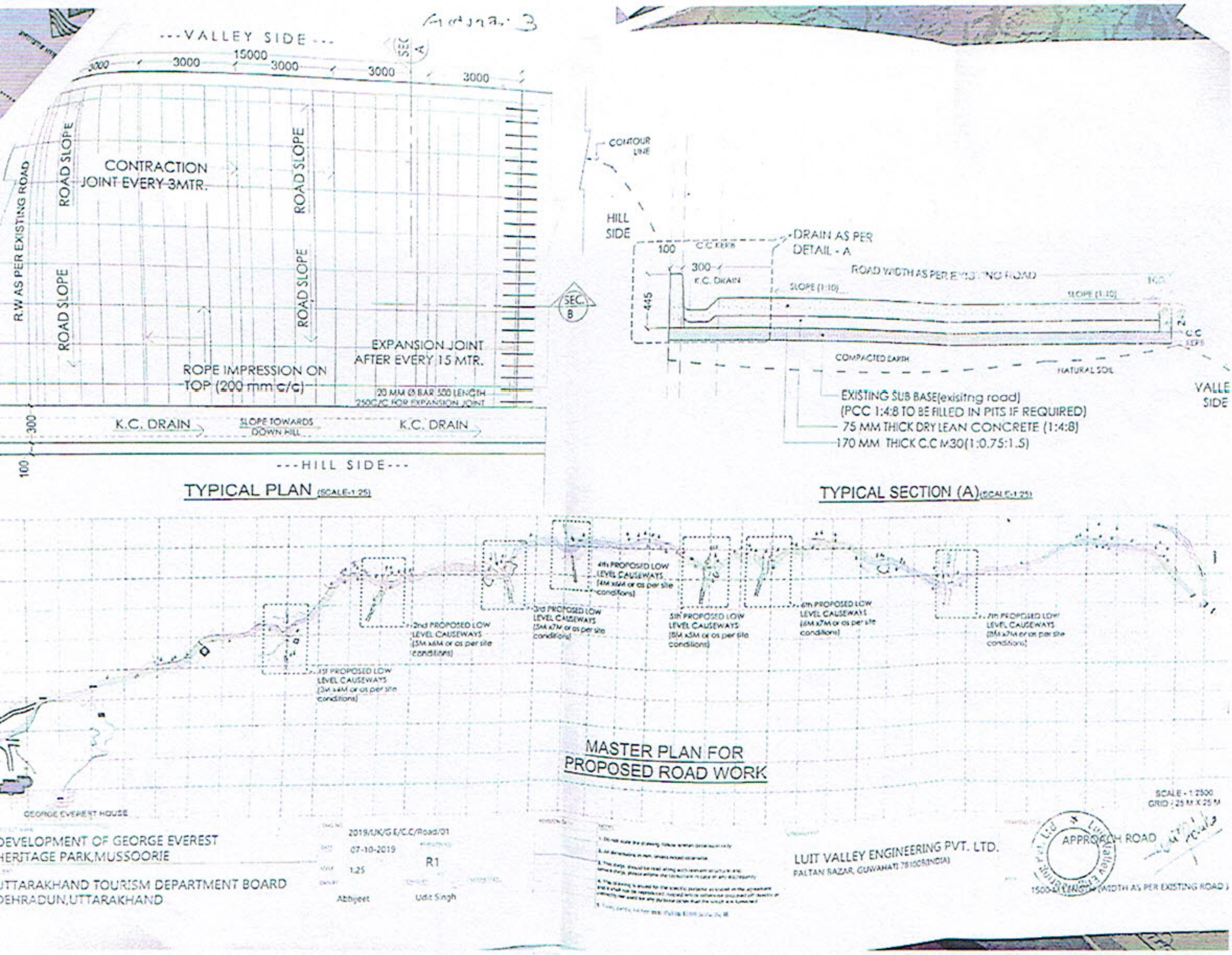

Scanned by CamScanner

संख्याः /X-3-20/1(11)/2020

सं0 173-5

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड,
उत्तराखण्ड देहरादून।

वन अनुभाग–3

देहरादूनः दिनांक 29 जनवरी, 2020

विषयः–जनपद देहरादून में जॉर्ज एवरेस्ट, मसूरी नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत प्राईवेट नोटिफाईड फॉरेस्ट मसूरी में पर्यटन विभाग की भूमि पर पर्यटकों की सुविधा व पर्यटन विकास के लिए 'जॉर्ज एवरेस्ट विरासत पार्क का विकास' हेतु 0.8886 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पर्यटन विकास विभाग को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रस्ताव अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा ऑन लाईन आई0डी0सं0–FP/UK /OTHERS/36509/2018, के माध्यम से भारत सरकार को प्रस्तुत (सब्मिट) किया जा चुका है, की हार्ड प्रति, राज्य सरकार की संस्तुति संबंधी प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के तहत भारत सरकार की स्वीकृति शीघ्र प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।

DFO Mussoorie

संख्याः 89 (1)/X-3-20/1(11)/2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को उनके पत्र संख्या–1659/FP/UK/OTHERS/36509/2018, दिनांक 08 जनवरी, 2019 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, जनपद–देहरादून।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
4. पर्यटन विकास विभाग, देहरादून।

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।

Scanned by CamScanner

(2-3)

No.11-2/98-FC(Pt.)/(196)(M)

संलग्नक-21

Government of India
Ministry of Environment & Forests

Paryavaran Bhawan
CGO Complex,
Lodi Road, New Delhi-110003

Dt. 28.02.2001

To

The Secretary (Forests)
Govt. of Uttaranchal
Dehradun

Sub: Clarification regarding applicability of Forest (Conservation) Act,1980 in respect of building construction of forest land(Private)in Mussoorie City of Uttar Pradesh(now Uttranchal).

Ref: This Office letter of even no. dated 31.3.2000 Site Inspection Report on illegal construction activities in Mussoorie.

Sir,

In continuation of the clarifications issued by this Ministry vide letter of even no. dated 31.3.2000 regarding applicability of Forest (Conservation) Act,1980 in respect of building construction on forest (private) land in Mussoorie City and with reference to site inspection report on illegal construction activities in Mussoorie carried out on 30.8.2000 by a team from MoEF and State Govt. officials including Vice Chairman, Mussoorie-Dehradun Development Authority I am directed to state that the Ministry further clarifies the following issues related with the circular dated 31.3.2000 on the subject mentioned above:

Issue-1

Whether reconstruction of buildings that were constructed before 25.10.80 could be permitted by MDDA without making any reference to Ministry of Environment & Forests (MoEF) except in those 16 estates in which the Supreme Court has refused permission to rebuilt properties under its order of 25.1.99 in W.P.No.469/96?

Sri Verma | Sri Aggarwal

Clarification

Reconstruction of building(s), partly or fully, may be permitted within the existing plinth area subject to permission under the local bye-laws only if the concerned local authorities certified that the building is unsafe for living and/or neighbouring structure(s). Reconstruction of such properties could be permitted with increase in built up area equivalent to 10% of the existing plinth area.

Scanned by CamScanner

Issue

Whether 10% increase allowed by MoEF in its order of 31.3.2000 in pre FCA(Forest Conservation Act) buildings in built up area (or the height) over and above the existing built up area is within the existing plinth area or anywhere within the plot owned by the party?

Clarification

MoEF will not have any objection if the pre- FCA properties are rebuilt/repaired/renovated provided these are permissible under the local by-laws/State Notification/Rules applicable to the area, there is no directions against reconstruction of such building(s) from the Supreme Court and there is no change of nature of its use. However, prior approval of the concerned local authorities (MDDA) has to be obtained. In doing so (i.e.rebuilding/repair/renovation) 10% increase in the overall existing plinth area could be considered by MDDA without making any reference to MoEF provided it is a case of reconstruction/repair/renovation and not a proposal for simple 10% addition in plinth area. Trees obstructing property's reconstruction/renovation/repair could be removed after prior approval of the competent authority (DFO) under the local Act like Tree Preservation Act.

Issue

Interpretation of para-4 (a to f) of MoEF letter no.11-2/98-FC(pt) dated 31.3.2000.

Clarification

Para-4(a)- refer clarification given above.

Para-4(b)- cases involving fresh forest land breaking beyond 10% of the existing built up area for rebuilding/repair/renovation would require prior approval of MoEF as per guidelines of FCA in force.

Para-4(c)- During the rebuilding/repair/renovation of properties (pre FCA) trees obstructing property's reconstructon/renovation/repair could be removed after prior approval of the competent authority (DFO) under the local Act like Tree Preservation Act.

Para 4(d)- Even in case of pre FCA properties if there is a change in the nature of use of the building no reconstruction/repair/renovation can be allowed without prior approval of MoEF.

Para-4(e)- Rebuilding/repair/renovation of properties is not allowed if there is any restriction under State Notification/rules/bye laws applicable to the site/area in Mussoorie.

Scanned by CamScanner

Para-4(f)- This condition is dropped i.e. no permission under the Doon Valley Notification is required for reconstruction/repair/renovation.

Issue

Over a period of time, buildings, which were constructed before 25.10.80 might have undergone changes in their plinth area. In such cases what should be the cut of date to permit 10% increase in built up area?

Clarification

Modalities should be worked by MDDA and the State Forest Department for residential buildings and educational institutions and a proposal should be sent to MoEF for decision.

Issue

How to handle the cases wherein use of building has been partly or fully changed from residential to commercial?

Clarification

In such cases any type of repair/renovation/ reconstruction should not be allowed without prior approval of MoEF. Such proposal(s) with necessary recommendations of the State Govt. should be sent to MoEF for consideration.

Issue

Existing educational institutions do require natural growth in terms of built up space, addition of new facilities etc. What should be the approach in such cases?

Clarification

No fresh construction in forest land should be allowed without prior approval of the Ministry of Environment & Forest. However, MDDA and the State Forest Deptt. should develop a procedure to cut delays in submitting complete proposal to MoEF for clearance as per guidelines of F.C.Act in force.

In addition to above clarification it is further suggested that:

construction of new hotels/resorts/lodges should not be allowed until Master Plan for Mussoorie is finalised and approved by the concerned authorities and MDDA issues guidelines on the type and extent of construction that could be taken up in Mussoorie. Guidelines for

Scanned by CamScanner

construction of residential buildings in terms of number of floors, opening of basement, size of the plot, and type of construction also need to be developed. Construction where slope is more than 30 should not be allowed. No large scale felling of mature trees (not more than 10) should be permitted. Equivalent compensatory plantation should be carried out within the plot area, if feasible. Major hill cutting should be avoided by carrying out construction on pillars. National Building Code may be referred to by MDDA while framing guidelines.

- Uttranchal Govt. should expedite demarcation of forest and non forest land in Mussoorie and notify them.,

- Master Plan for Mussoorie should be finalised on priority.

- Details pertaining to buildings constructed before 25.10.1980 and subsequent changes that have in the plinth area need to be documented. As on date no information is available on Khasra No./Khatoni No./ Survey No. of properties in Mussoorie. MDDA should up date their records and notify the same within one year.

- Reconstruction of old Estates properties may be permitted alog with a maximum of 10% in pre FCA built up area subject to local bye laws and clarification from the Supreme Court in respect of order of 25.1.99 in W.P.No.469/96.

Yours faithfully,

(Sanjukta Patnaik)
Asstt. Inspector General of Forests

Copy to:

1. PCCF, Govt. of Uttranchal, Dehradun
2. CCF(C), Regional Office, Lucknow.
3. Nodal Officer, Office of PCCF, Govt. of Uttranchal Dehradun.

Sanjukta Patnaik 25/02

(Sanjukta Patnaik)
AIGF

Scanned by CamScanner

No. 11-2/98-FC(Pt)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

PARYAVARAN BHAWAN, CGO COMPLEX,
LODI ROAD, NEW DELHI-110 003.

Dated 31.03.2000

To,

The Secretary (Forests),
Govt. of Uttar Pradesh,
Lucknow.

Subject: Clarification regarding applicability of Forest (Conservation) Act, 1980 in respect of building construction on forest (private) land in Mussoorie City of Uttar Pradesh.

Sir,

In suppression of this Ministry's letter of even no. dated 26th June 1999 on above mentioned subject I am directed to say that this Ministry through its Regional Office (Lucknow) has received large number of proposals from State Government for seeking approval of Central Government under Forest (Conservation) Act, 1980 for regularization/repair/ renovation of buildings on private forest/forest land in Mussoorie city.

It is mentioned in the proposal that these have been submitted by the State Government as per the orders of Supreme Court in writ petition No. 749/95 in the matter of SCMC Vs. MDDA and Others. In above writ petition, Hon'ble Supreme court has taken cognizance of building construction on private forest land in Mussoorie in violation of provisions of F(C) Act, 1980. The apex Court ordered inter-alia that State Government will forward all such cases to Central Government for seeking ex-post facto approval and Central Government will process these proposals in accordance with the rules framed under the 1980 Act, without making any final order.

The Ministry has received several representations saying that the provisions of F(C) Act are not correctly applied while formulating/submitting proposals by the State Government. It seems that there is some lack of clarity regarding applicability of the provisions of the act in respect of construction of buildings etc., forest/private forest in Mussoorie. Therefore, this Ministry has felt it necessary to clarify/reiterate provisions of F(C) Act regarding its applicability in such cases.

Scanned by CamScanner

1. In some of the proposals, it was noticed that proposals have been submitted of land which is not notified private forest land. If it is not a forest as per revenue record, it has to be "Forest" as per dictionary sense to attract provisions of F(C) Act. However, in such cases, State Government must enclose a certificate that this land has been identified by the Expert Committee and is listed in the affidavit filed by the State Government in Apex Court in W.P. No. 202/95.

2. In respect of proposals seeking ex-post facto approval of Central Government and for carrying out repair/renovation etc., of building which was constructed in violation of F(C) Act, it is clarified that if State Government comes to conclusion that there is violation of F(C) Act and approval of Central Government is required then proposals for seeking ex-post facto approval of Central Government as per direction of Hon'ble Supreme Court should be submitted. As per direction of apex court, State Government has already been asked to provide certain information e.g. cases where inquiry/investigation is going on the complaints of irregularities and certificate that there is no violation of MBA/MDDA by-laws and cases are free from extraneous consideration. The report of State Government on this account is still awaited in spite of several reminders. Once these information are provided by State Government, proposals will be processed as per the directions of Hon'ble Supreme Court.

3. In respect of proposal of new construction of building on forest land, it is clarified that F(C) Act is attracted for all types of forests including dictionary sense and certificate as mentioned in para 1 of this letter should be enclosed. All such proposals will be processed as per the guidelines of F(C) Act, 1980 in force.

4. Cases for repair/renovation/reconstruction on existing plinth area where the main building was constructed before 25.10.1980 (i.e. when the Act came into force) and permission under prevailing rules/regulations was obtained for such construction, general permission under Forest (Conservation) Act, 1980 is given subject to following criteria being satisfied/fulfilled:

(a) Repair/Renovation/Reconstruction is limited on existing plinth area and the increase in built up area or the height over and above the existing built up area is not more than 10%.
(b) There is no breaking of fresh forest land.
(c) No felling of trees are involved
(d) There is no change in nature of its use.
(e) It is not prohibited by any other State Notification/ Rules/By laws in that area.
(f) Permissable under Doon Valley Notification.

However, permission under other by-laws of local authority will have to be obtained.

Scanned by CamScanner

5. Your kind attention is also drawn to direction of Hon'ble Supreme Court in Writ Petition No. 469/96 dated 25.1.99 to ensure compliance where permission for rebuilding of properties in Mussoorie has been refused.

6. You are requested to re-examine all the proposals submitted for seeking approval of Central Government under F(C) Act in light of the above clarification and furnish necessary information as mentioned above to CCF(C), Lucknow and take suitable action to ensure correct application of F(C) Act.

Yours faithfully,

(V.B. KUMAR)
ASSTT. INSPECTOR GENERAL OF FORESTS (FC)

Copy to :-

1. PCCF, State Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.
2. CCF(C), Regional Office, Lucknow for suitable necessary action.
3. Nodal Officer, Office of PCCF, Lucknow.

V.B. Kumar 31/3
(V.B. KUMAR)
ASSTT. INSPECTOR GENERAL OF FORESTS (FC)

4078/ dt. 13-4-2000

Copy to P.C.C.F. Uttaranchal, Nainital for information & necessary action.

[signature] 13/4/2001
Nodal Officer
U.P. Lucknow

4078/ [illegible] dt. 13-4-2000

Copy to the following officers of U.P. Forest Department for informing their concerned officers for necessary action in this respect.

1. C.C.F. Kumaon, Mallital Nainital
2. C.C.F. Garhwal, Rajpur Road, Dehradun.

[signature] [illegible]/2000
Nodal officer
U.P. Lucknow

Scanned by CamScanner